International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

हरियाणा के सोनीपत और रोहतक जिलों में कृषक समाज: परंपरा से आधुनिकता तक (1966–2010)

सचिन
शोधार्थी, इतिहास विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर रोहतक
डॉ राजबीर सिंह गुलिया
प्रोफेसर, इतिहास विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर रोहतक

सारांश
यह शोध पत्र हरियाणा के सोनीपत और रोहतक जिलों में 1966 से 2010 तक कृषक समाज में आए निरंतरता और परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ, और इसी वर्ष हरित क्रांति की शुरुआत भी मानी जाती है। यह अध्ययन दर्शाता है कि किस प्रकार हरित क्रांति, भूमि सुधार, तकनीकी प्रगति, और 1990 के दशक के उदारीकरण ने इन दो जिलों के कृषक समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को मूल रूप से बदल दिया। अध्ययन में पाया गया कि हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि की, लेकिन साथ ही वर्ग विभेद, जातिगत असमानता और भूमि-केंद्रित सत्ता संरचनाओं को भी मजबूत किया। 1990 के बाद की उदारीकरण नीतियों ने कृषि को पूंजीवादी स्वरूप प्रदान किया, जिससे लघु और सीमांत किसानों का विस्थापन हुआ और कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। सोनीपत में शहरीकरण और औद्योगीकरण ने कृषि भूमि के रूपांतरण को तेज किया, जबकि रोहतक में कृषि आधुनिकीकरण और जातिगत सत्ता संरचनाओं में निरंतरता देखी गई। यह पत्र तर्क करता है कि इन दो जिलों में "परंपरा से आधुनिकता" का संक्रमण न तो रैखिक था और न ही सर्वसमावेशी; यह असमान, विरोधाभासी और जाति-वर्ग-लिंग द्वारा मध्यस्थ था।

मुख्य शब्द: कृषक समाज, हरित क्रांति, भूमि सुधार, उदारीकरण, सोनीपत, रोहतक, हरियाणा

प्रस्तावना

हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ। इसी वर्ष भारत में हरित क्रांति की औपचारिक शुरुआत भी मानी जाती है, जब उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYV) के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की नई तकनीकों का व्यापक प्रसार हुआ। हरियाणा, जो पहले पंजाब का हिस्सा था, हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य बना। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में 1966 से 2010 के बीच गहन संरचनात्मक

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

परिवर्तन हुए, जिन्होंने कृषक समाज के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को मौलिक रूप से प्रभावित किया।[i]

सोनीपत और रोहतक, हरियाणा के दो महत्वपूर्ण जिले, इस परिवर्तन के विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सोनीपत, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के निकट स्थित है, ने 1990 के दशक के बाद तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण का अनुभव किया, जिससे कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर औद्योगिक और आवासीय उपयोग में रूपांतरण हुआ। दूसरी ओर, रोहतक, जो ऐतिहासिक रूप से जाट बहुल कृषि क्षेत्र रहा है, ने हरित क्रांति के लाभों को आत्मसात किया, लेकिन साथ ही भूमि-आधारित जातिगत सत्ता संरचनाओं में निरंतरता भी बनाए रखी।

साहित्य समीक्षा

हरियाणा के कृषक समाज पर विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन किया है। शीला भल्ला (1974) ने हरित क्रांति के प्रभावों का अग्रणी अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि नई तकनीक ने संयुक्त परिवार प्रणाली को विघटित किया और भूमि जोतों का विभाजन किया।[ii] भल्ला (1977) ने यह भी पाया कि हरित क्रांति के बाद कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई और स्थायी श्रमिकों ('नौकर') की एक नई श्रेणी उभरी।[iii]

सुरिंदर एस. जोधका (2014) ने हरियाणा के दो गांवों का 20 वर्षों के अंतराल पर पुनः अध्ययन करके दिखाया कि हरित क्रांति और बाद में बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाओं ने ग्रामीण जीवन को कैसे बदल दिया। उन्होंने जाति और वर्ग संबंधों में परिवर्तन, शहरी केंद्रों के साथ गांवों के बदलते संबंध, और स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में सत्ता संबंधों के उभरते स्वरूप का विश्लेषण किया।[iv]

जोधका (2011) ने यह भी दर्शाया कि हरियाणा में भूमि का अधिकांश हिस्सा जाटों के नियंत्रण में था, जो आबादी में भी संख्यात्मक रूप से मजबूत थे। अन्य कृषक जातियों में अहीर, गुज्जर और सैनी शामिल थे। इन कृषक जातियों की आबादी लगभग 51% थी, लेकिन वे 80% भूमि को नियंत्रित करती थीं।[v]

परमजीत सिंह और मुकेश कुमार (2025) ने हरियाणा में किरायेदारी की गतिशीलता का विश्लेषण करते हुए दिखाया कि गरीब और छोटे किसान आर्थिक संकट के कारण "भूख (निर्वाह) पट्टे" पर भूमि लेते हैं, जबकि धनी किसान संचय के लिए पट्टे पर भूमि लेते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उदारीकरण के बाद भी किरायेदारी शोषण बना हुआ है।[vi]

नवीन सिंह ने हरियाणा में हरित क्रांति के बाद के कृषि विकास का विश्लेषण करते हुए दिखाया कि सिंचाई और बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ-साथ फसल पद्धति में परिवर्तन हुआ, लेकिन फसल संरचना में विविधीकरण नहीं हो सका। उन्होंने यह भी पाया कि भूमि और श्रम उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन असमानताएं भी बढ़ीं।[vii]

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

हरियाणा के जिला राजपत्रों (गजेटियर्स) और सांख्यिकीय सारांशों से यह स्पष्ट होता है कि 1966 से पहले सोनीपत और रोहतक की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित थी। सोनीपत में 1981 की जनगणना के अनुसार 59.40% मुख्य श्रमिक कृषक और कृषि श्रमिक थे।[viii] रोहतक में 1961 में अनुसूचित जातियों की आबादी 17.2% थी, जिनमें चमार सबसे बड़ी संख्या में थे ।[ix]

हरित क्रांति से पूर्व कृषक समाज: परंपरागत व्यवस्था (1966 से पहले)

1966 से पहले, सोनीपत और रोहतक की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः निर्वाह कृषि पर आधारित थी। सोनीपत में कृषि के साथ-साथ पशुपालन और कुटीर उद्योग भी प्रचलित थे। बुनकर, बढ़ई, लोहार, कुम्हार जैसे कारीगर गांवों में मौजूद थे, जो अनाज के हिस्से के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, और मुद्रा का प्रयोग सीमित था।

रोहतक जिले में भूमि का स्वामित्व मुख्यतः जाटों के पास था, हालांकि ब्राह्मण, राजपूत और अन्य कृषक जातियां भी भूमि जोतती थीं। भूमि संबंधों में जमींदार, पट्टेदार और किरायेदार जैसी श्रेणियां मौजूद थीं। 1910 और 1947 के बीच भूमि धारण प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला लागू की गई। पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम (1949), पंजाब अला मलिकियत और तालुकदारी अधिकार उन्मूलन अधिनियम (1952), पंजाब किरायेदार (स्वामित्व अधिकार) अधिनियम (1952), और पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम (1953) प्रमुख थे। इन कानूनों ने बिचौलियों को समाप्त करने और किरायेदारों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने का प्रयास किया। 1966 तक रोहतक में 1,740 अधिशेष भूमि के मामले निपटाए गए और 21,041 मानक एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई । हालांकि, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन असमान रहा, और बड़े भूमि स्वामियों ने कानूनी खामियों का लाभ उठाकर अपनी जोतें बचाई रखीं।[x]

हरित क्रांति और कृषि आधुनिकीकरण (1966–1990)

हरित क्रांति ने सोनीपत और रोहतक की कृषि में अभूतपूर्व तकनीकी परिवर्तन लाए। 1966-67 में सिंचाई का मुख्य साधन नहरें थीं और जुताई के लिए बैल का उपयोग होता था। 2009-11 तक नहरों की लंबाई 971.5 किमी से बढ़कर 1214.5 किमी हो गई, और ट्यूबवेलों की संख्या 0 से 1764.5 प्रति हजार हेक्टेयर हो गई। ट्रैक्टरों की संख्या में 2993.6% की वृद्धि हुई। उर्वरकों की खपत में 6579.7% और कीटनाशकों की खपत में 1108.6% की वृद्धि दर्ज की गई। फसल पद्धति में भी बड़ा बदलाव आया। मोटे अनाज और दालों से चावल और गेहूं की ओर किसानों का झुकाव बढ़ा। रोहतक और सोनीपत दोनों जिलों में चार फसल

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

संयोजन देखे गए।[xi] सोनीपत में 1976-77 में सिंचाई की तीव्रता 68.97% थी, जो बाद में बढ़ी। सोनीपत में ट्रैक्टरों का घनत्व 1976-77 में 8.6 से बढ़कर 59.02 हो गया।

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन

हरित क्रांति ने कृषक समाज के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। शीला भल्ला ने पाया कि हरित क्रांति ने संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन को गति दी, क्योंकि नई तकनीक से प्रति एकड़ आय बढ़ी, जिससे संयुक्त परिवार को एक साथ रखने वाली आर्थिक बाध्यता समाप्त हो गई ।

किरायेदारी में उल्लेखनीय कमी आई। हरियाणा में 1970-71 में 7.97% कृषि भूमि किरायेदारी पर थी, जो 1976-77 तक घटकर 2.7% रह गई । बड़े किसानों ने स्वयं खेती के लिए भूमि वापस लेना शुरू किया। जो किरायेदार अपनी भूमि खो बैठे, वे कृषि श्रमिकों की श्रेणी में शामिल हो गए। कृषि श्रमिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कृषि में श्रमिकों का अनुपात कुल कार्यबल का 1961 में 6.9% से बढ़कर 1971 में 16.21% हो गया । 1991 तक यह बढ़कर 19.38% हो गया। भल्ला ने पाया कि आधे से अधिक कृषि श्रमिक स्थायी श्रमिक थे, और 'नौकर' नामक एक नई श्रेणी उभरी। बिहार और उत्तर प्रदेश से प्रवासी श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि हुई, क्योंकि हरियाणा में मजदूरी दरें अधिक आकर्षक थीं।[xii]

जाति और वर्ग विभेद

हरित क्रांति के लाभ असमान रूप से वितरित हुए। बड़े और मध्यम किसानों, जिनके पास अधिक भूमि, सिंचाई, पूंजी और आधुनिक तकनीक तक पहुंच थी, ने अनुपातिक रूप से अधिक लाभ प्राप्त किया और आर्थिक व राजनीतिक रूप से प्रभुत्वशाली बने। छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिक हाशिये पर रह गए, जिनकी आय, रोजगार के अवसर और सामाजिक गतिशीलता सीमित रही।

जाट, जो पहले से ही भूमि के प्रमुख स्वामी थे, हरित क्रांति के मुख्य लाभार्थियों में से थे। जोधका (2011) के अनुसार, हरियाणा में कृषक जातियों (जाट, अहीर, गुज्जर, सैनी) की आबादी लगभग 51% थी, लेकिन वे 80% भूमि को नियंत्रित करती थीं। अनुसूचित जातियों, विशेषकर चमारों, की स्थिति में सुधार सीमित रहा। रोहतक जिले में 1961 में अनुसूचित जातियों की आबादी 2,43,958 थी, जो कुल जनसंख्या का 17.2% थी। इनमें से अधिकांश कृषि श्रमिक या पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए थे।

मशीनीकरण ने उत्पादकता बढ़ाई लेकिन श्रम की मांग कम की, जिससे ग्रामीण असमानताएं और तीव्र हुईं। हरित क्रांति ने हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था को बदल दिया, लेकिन साथ ही वर्ग ध्रुवीकरण को गहरा किया, पारंपरिक सामाजिक एकजुटता को कमजोर किया और संरचनात्मक असमानता को मजबूत किया।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

उदारीकरण और नव-उदारवादी मोड़ (1991–2010)

आर्थिक नीतियों में परिवर्तन

1991 में भारत ने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के तहत आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें कृषि क्षेत्र का उदारीकरण भी शामिल था। हरियाणा में नव-उदारवादी सुधारों ने कृषि में विस्थापन और सर्वहारीकरण की प्रक्रिया को जन्म दिया। बाजार-आधारित कृषि आदानों के उपयोग में वृद्धि हुई और सभी किसान वर्गों में ऋणग्रस्तता बढ़ी। पूंजीवाद का उच्च स्तर और असमानता बनी रही। कृषि में रोजगार की वृद्धि दर 1980 और 1990 के दशक में अधिक थी, लेकिन उसके बाद उदारीकृत अर्थव्यवस्था के प्रभाव से कृषि और संबंधित उद्योगों में रोजगार में कमी आई ।[xiii]

सोनीपत: शहरीकरण और भूमि रूपांतरण

सोनीपत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के निकट होने के कारण, 1990 के दशक के बाद तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण का केंद्र बन गया। कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय उपयोग में रूपांतरण हुआ । सोनीपत जिले में 2005-06 से 2011-12 के बीच कृषि भूमि के उपयोग में 5% से अधिक की कमी दर्ज की गई । सोनीपत शहर के परिधि क्षेत्रों में 1991 से 2001 के बीच कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर अन्य उपयोगों में रूपांतरण हुआ । सोनीपत में कुछ गांवों के किसानों ने गहन कृषि पद्धतियों और खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश किया, जिससे गांव के भीतर आय और रोजगार के अवसर पैदा हुए। हालांकि, कई गांवों से युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन भी हुआ ।[xiv]

सोनीपत में 1951 में एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज की स्थापना के बाद से औद्योगिक विकास शुरू हुआ था, लेकिन 1990 के बाद यह प्रक्रिया तेज हुई। 1989 में जिले में 162 पंजीकृत कार्यशील कारखाने थे, जिनमें 12,281 श्रमिक कार्यरत थे।

रोहतक: कृषि आधुनिकीकरण और जातिगत निरंतरता

रोहतक में उदारीकरण का प्रभाव सोनीपत से भिन्न रहा। यहां कृषि आधुनिकीकरण जारी रहा, लेकिन भूमि-आधारित जातिगत सत्ता संरचनाओं में अधिक निरंतरता देखी गई। रोहतक में जाटों का भूमि पर प्रभुत्व बना रहा, और खाप पंचायतों जैसी पारंपरिक संस्थाओं का प्रभाव भी बना रहा।[xv] रोहतक में कृषि श्रमिकों की स्थिति में सीमित सुधार हुआ। 2010-11 में रोहतक को मध्यम कृषि श्रमिक वाले जिलों की श्रेणी में रखा गया। भूजल की गुणवत्ता और उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी रही, क्योंकि हरित क्रांति के बाद सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ी ।[xvi] रोहतक में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के रूप बने रहे। 1961 की जनगणना के अनुसार, रोहतक में अनुसूचित जातियों में चमारों की संख्या सबसे अधिक (1,21,124) थी,

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

इसके बाद बाल्मीकि (61,136) और धानक (46,586) थे। इन समुदायों के मुख्य व्यवसाय कृषि श्रम, बुनाई, चमड़ा टैनिंग, जूता बनाना, सफाई और अनाज भूनना थे ।[xvii]

निरंतरता और परिवर्तन: तुलनात्मक विश्लेषण

सोनीपत और रोहतक दोनों जिलों में 1966 से 2010 के बीच कृषक समाज में गहरे परिवर्तन हुए, लेकिन इनकी गति और दिशा भिन्न रही।

तालिका 1: सोनीपत और रोहतक में प्रमुख परिवर्तनों की तुलना (1966–2010)

पहलू	सोनीपत	रोहतक
कृषि भूमि का उपयोग	तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण कृषि भूमि में कमी	कृषि भूमि का अधिकांश हिस्सा कृषि के अधीन बना रहा
मुख्य आर्थिक गतिविधि	कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्र में विविधीकरण	कृषि और संबद्ध गतिविधियों में निरंतरता
जातिगत संरचना	औद्योगीकरण से जातिगत बंधनों में कुछ ढील	जाट भूमि-सत्ता में निरंतरता, खाप पंचायतों का प्रभाव
कृषि श्रमिकों की स्थिति	औद्योगिक रोजगार के अवसरों से कुछ सुधार	कृषि श्रम में निरंतरता, सीमित गतिशीलता
भूमि उपयोग में परिवर्तन	1991 के बाद तीव्र भूमि रूपांतरण	भूमि उपयोग में अपेक्षाकृत स्थिरता
सिंचाई	ट्यूबवेल और नहर सिंचाई का व्यापक विस्तार	भूजल पर अत्यधिक निर्भरता, गुणवत्ता की समस्या

सोनीपत में, NCR के निकटता और औद्योगिक विकास ने कृषि भूमि के रूपांतरण को तेज किया, जिससे पारंपरिक कृषक समाज का ताना-बाना बदल गया। दूसरी ओर, रोहतक में, कृषि आधुनिकीकरण जारी रहा, लेकिन भूमि-आधारित जातिगत सत्ता संरचनाओं में अधिक निरंतरता देखी गई। दोनों जिलों में, हरित क्रांति और उदारीकरण ने वर्ग विभेद को गहरा किया और छोटे किसानों व भूमिहीन श्रमिकों को हाशिये पर धकेला।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि हरित क्रांति ने सोनीपत और रोहतक की कृषि में तकनीकी आधुनिकीकरण को गति दी और उत्पादकता बढ़ाई, परंतु इसके लाभ असमान रूप से वितरित हुए। भूमि सुधारों ने किरायेदारी को कम किया, लेकिन बड़े भूमि स्वामियों का प्रभुत्व बना रहा; जाट, अहीर, गुज्जर और सैनी जैसी कृषक जातियों ने भूमि और सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। 1991 के बाद की उदारीकरण नीतियों ने कृषि में पूंजीवादी विकास को बढ़ावा दिया, जिससे विस्थापन और सर्वहारीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। सोनीपत

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

में शहरीकरण और औद्योगीकरण ने कृषि भूमि के रूपांतरण को तेज किया, जबकि रोहतक में कृषि तथा जातिगत सत्ता संरचनाओं में अधिक निरंतरता देखी गई। दोनों जिलों में अनुसूचित जातियों और छोटे किसानों की स्थिति में सीमित सुधार हुआ, और मशीनीकरण ने श्रम की मांग कम करके कृषि श्रमिकों की स्थिति को कमजोर बनाया। इस प्रकार "परंपरा से आधुनिकता" का संक्रमण न तो रैखिक था और न ही सर्वसमावेशी; यह असमान, विरोधाभासी तथा जाति–वर्ग–लिंग द्वारा मध्यस्थ रहा। यह अध्ययन दर्शाता है कि हरियाणा के कृषक समाज में निरंतरता और परिवर्तन की प्रक्रिया जटिल और बहुआयामी रही है; भविष्य के शोध में इन जिलों में लिंग संबंधों, पर्यावरणीय प्रभावों और कृषि संकट के सामाजिक आयामों का और गहन अध्ययन किया जा सकता है।

---

[i] सिंह, एन. रीसेंट डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर: द हरियाणा एक्सपीरियंस. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट्स

[ii] भल्ला, एस. (1974) चेंजिंग एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन इंडिया: अ स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन हरियाणा. पंजाब यूनिवर्सिटी

[iii] भल्ला, एस. (1977) न्यू रिलेशन्स ऑफ प्रोडक्शन इन हरियाणा एग्रीकल्चर. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 12(13), A23–A30

[iv] जोधका, एस. एस. (2014). व्हाट्स हैपनिंग टू द विलेज? रीविजिटिंग रूरल लाइफ एंड एग्रेरियन चेंज इन हरियाणा (सीएएस वर्किंग पेपर सीरीज़, CAS/WP/14-1) सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी

[v] जोधका, एस. एस. (2011) कास्ट एंड पावर इन द लैंड्स ऑफ एग्री-कल्चर. स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन

[vi] सिंह, पी., और कुमार, एम. (2025). क्लास डायनैमिक्स ऑफ टेनेंसी एंड एक्युमुलेशन इन कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया. जर्नल ऑफ एग्रेरियन चेंज. https://doi.org/10.1111/joac.70051

[vii] सिंह, एन. रीसेंट डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर: द हरियाणा एक्सपीरियंस. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट्स

[viii] हरियाणा सरकार (1990) सोनीपत डिस्ट्रिक्ट गजेटियर. आर्काइव.ऑर्ग. https://archive.org/download/dli.csl.2857/2857_text.pdf

[ix] हरियाणा सरकार. (1970). हरियाणा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स: रोहतक. आर्काइव.ऑर्ग. https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.532522/2015.532522.haryana-district_djvu.txt

[x] सिंह, वीरेंद्र. (2006) रूरल डेवलपमेंट एंड डेट: मोड एंड एक्सटेंट ऑफ इंडेब्टेडनेस इन हरियाणा_अ केस स्टडी (अध्याय-2). महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय. शोधगंगा https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/51235/7/07_chapter%202.pdf

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

[xi] कौर, अपरदीप. (2020). इम्प्लीकेशन्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी इन द एग्रो इकोसिस्टम्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा शोधगंगा https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/341674/4/13.chapter-7.pdf

[xii] भल्ला, एस. (1977). न्यू रिलेशन्स ऑफ प्रोडक्शन इन हरियाणा एग्रीकल्चर. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 12(13), A23–A30

[xiii] अ क्लास एनालिसिस ऑफ एग्रेरियन कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इन हरियाणा. (2021). स्किलिट

[xiv] द अर्बन विलेज, एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड रेंटियर कैपिटलिज़्म इन गुरगांव, इंडिया. (2018). एंटीपोड.

[xv] कैनेडी, एल. (2023). द पॉलिटिक्स ऑफ लैंड एक्विजिशन इन हरियाणा: मैनेजिंग डॉमिनेंट कास्ट इंटरेस्ट्स इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. एचएएल ओपन साइंस

[xvi] सिंह, आर. बी. (2014). सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. स्प्रिंगर

[xvii] हरियाणा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स: रोहतक. आर्काइव.ऑर्ग